>

Title: The Minister of Rural Development made a statement regarding the Nirmal Gram Puraskar, 2007.

ग्रामीण विकास मंत्री (डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस महान सदन को यह जानकारी देते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज महामहिम डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, भारत के राष्ट्रपति द्वारा देश में स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायती राज संस्थाओं/गैर-सरकारी संगठनों को तीसरा निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया जा रहा है। निर्मल ग्राम पुरस्कार के लिए श्रेष्ठ गांवों और ग्रामीण स्वच्छता के अनुकरणीय उदाहरणों का चयन किया जाता है।

निचले स्तर पर कार्यरत स्टेकहोल्डरों, पंचायती राज संस्थाओं/गैर-सरकारी संगठनों के बीच सामाजिक जागृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में पूर्ण स्वच्छता कवरेज हासिल करने पर निर्मल ग्राम पुरस्कार के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है। खुले में शौच की पूथा से पूर्णतः मुक्त, गांवों में समुचित स्वच्छता कवरेज हासिल करने वाली तथा पूरी तरह से साफ-सफाई रखने वाली पंचायती राज संस्थाएं इस पुरस्कार की हकदार होती हैं। वित्तीय प्रोत्साहन की राशि जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायतों के लिए 50,000 रुपये से लेकर पाँच लाख रुपये, ब्लाक पंचायतों के लिए 10 लाख रुपये से लेकर 20 लाख रुपये तथा जिला पंचायतों के लिए 30 लाख रुपये से 50 लाख रुपये है।

निर्मल ग्राम पुरस्कार वर्ष 2005 में शुरू किया गया था जिसके दौरान 40 पंचायती राज संस्थाओं को यह पुरस्कार दिया गया था। दूसरा समारोह 2006 में आयोजित किया गया था जिसमें 769 पंचायती राज संस्थाओं को सम्मानित किया गया था। यह गर्व का विषय है कि चालू वर्ष के दौरान 22 राज्यों से लगभग 4945 ग्राम पंचायतों, 14 ब्लाक पंचायतों तथा 27 गैर-सरकारी संगठनों को यह पुरस्कार दिया जा रहा है। (राज्य-वार ब्यौरे संलग्न में दिया गया हैं।)

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वच्छता के महत्व का विशेष उल्लेख किया जब उन्होंने यह कहा कि "स्वच्छता स्वतंत्रता से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।" वर्ष 1981 की जनगणना में हमारे देश के केवल 1 प्रतिशत परिवारों ने ही स्वच्छता कवरेज हासिल की थी। [H1]

*Statement alongwith state-wise details were placed in Library. See No L.T. 6278/2007

1991 की जनगणना में ये आंकड़े नौ प्रतिशत तक और 2001 की जनगणना में 21.9 प्रतिशत तक पहुंच गए हैं। इसके बाद मांग आधारित दÂिटकोण के साथ पुनर्गठित केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत संपूर्ण स्वच्छता अभियान शुरु किया गया। अब यह कार्यक्रम भारत सरकार, संबंधित राज्य सरकारों की सहायता तथा स्वयं लाभार्थियों के अंशदान से देश के 572 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। अब तक 11375 करोड़ रु. की लागत वाली परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। भारत सरकार ने कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए पहले ही 2280 करोड़ रु. की राशि रिलीज़ कर दी है। स्वीकृत परियोजनाओं में गरीबी रेखा से नीचे तथा गरीबी रेखा से ऊपर के लाभार्थियों के परिवारों के लिए अलग-अलग घरेलू शौचालय तथा विद्यालयों/बालवाड़ियों/आंगनवाड़ियों इत्यादि के लिए स्वच्छता परिसरों की व्यवस्था की गई है। फिर भी हमारे इस अभियान का उद्देश्य केवल शौचालय बनाना ही नहीं, बल्कि हमारा उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में साफ-सफाई की बेहतर प्रक्रियाओं पर निरंतर बल देना है।

संपूर्ण स्वच्छता अभियान की सहायता से अब तक 3.16 करोड़ परिवारों ने स्वच्छ शौचालय बना लिए हैं। मात्र पिछले तीन वÂा◌ा◌ों में 2.36 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय कवरेज़ में उल्लेखनीय वृद्धि का द्योतक है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान के प्रयासों के परिणामस्वरूप घरेलू स्वच्छता कवरेज़ 44 प्रतिशत तक पहुंच गई है। मंत्रालय को यह उम्मीद है कि स्वर्णिम विकास लक्ष्य को निर्धारित समय-सीमा से पहले ही हासिल कर लिया जाएगा। इस पुरस्कार ने समूचे कार्यक्रम को जन-आंदोलन में परिवर्तित करके संपूर्ण स्वच्छता अभियान के महत्व को बढ़ा दिया है।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन से मेरी प्रार्थना है कि उसमें सभी माननीय सदस्य आमंत्रित हैं। यह राज्यवार है, एक मिनट में हो जाएगा।...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Please lay that on the Table. We must compliment those panchayats and those people who are being recognized properly. I am sure, this will inspire other panchayats also to follow that. This is very good.

STATEMENT DETAILS *

क्र. सं.	राज्य	2005 पंचायती राज संस्थाओं की संख्या	2006 पंचायती राज संस्थाओं की संख्या	2007 पंचायती राज संस्थाओं की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	-	10	143
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	-	2

3.	असम	-	1	3
4.	बिहार	-	4	39+1(ब्लाक)
5.	छत्तीसगढ़	-	12	90
6.	गुजरात	1	4	576
7.	हरियाणा	-	-	60
8.	हिमाचल प्रदेश	-	-	22
9.	झारखंड	-	-	12
10.	कर्नाटक	-	-	121
11.	केरल	1	6	220+6(ब्लाक)
12.	मध्यप्रदेश	-	1	190
13.	महाराष्ट्र	13	381	1974
14.	मिजोरम	-	-	3
15.	उडीसा	-	8	33
16.	राजस्थान	-	-	23
17.	सिक्किम	-	-	27
18.	तमिलनाडु	13	119	296
19.	त्रिपुरा	1	36	46
20.	उत्तर प्रदेश	-	40	488
21.	उत्तरांचल	-	13	109
22.	पश्चिम बंगाल	11	134	468+7(ब्लाक)
	कुल	40	769	4,945 ग्राम पंचायत+14 ब्लाक *

â€¦ Statewise details were laid on the Table.